



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2006/आषाढ़ 13, 1928

No. 146]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2006/ASADHA 13, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2006

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय :— चीन जन. गण. से पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/10/2005-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) एवं सीमाशुल्क टैरिफ (क्षति निर्धारण हेतु पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन एवं पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

- जबकि घरेलू उत्पादकों, नामतः मैसर्स अर्फीस इंडस्ट्रीज लि., मै. अपोलो फाइबर्स लि., मै. सेंट्रल इंडिया पॉलिएस्टर्स लि., मै. सेंच्युरी एन्का लि., मै. फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज लि., मै. गार्डन सिल्क मिल्स लि., मै. इंडो. रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लि., मै. जेबीएफ लि., मै. मॉर्डन पेट्रोफिल्स लि., मै. नकोड़ा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लि., मै. रेक्रॉन सिंथेटिक्स लि. एवं मै. वेलस्पन सिन्टेक्स लि. की ओर से मै. एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज (जिसे एतदपश्चात याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा सीमाशुल्क

टैरिफ अधिनियम एवं पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें चीन जन.गण.(जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया ।

3. और जबकि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 13 दिसंबर, 2005 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया और नियमावली के नियम-6 के अनुसरण में कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव के निर्धारण हेतु और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई ।

क. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत को अधिसूचित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई ।
 - (i) प्राधिकारी द्वारा ऊपर उल्लिखित नियम-5 के उप-नियम (5) के अनुसरण में जांच प्रारंभ करने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पाटन याचिका की प्राप्ति के संबंध में संबद्ध देश के भारत स्थित दूतावास को अवगत कराया गया ;
 - (ii) प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा याचिकाकर्ता को अग्रेषित की गई और नियम 6(2) के अनुसरण में जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उन्हें अपने विचार लिखित में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ;
 - (iii) बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने के लिए सभी ज्ञात निर्यातकों तथा चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को एक प्रश्नावली भिजवाई गई । जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ ताईवान में

सामान्य मूल्य के उपयुक्त अनुमान के रूप में संरचित सामान्य मूल्य को आधार बनाया गया। भारत के संदर्भ में किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था की कीमत के विकल्प के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 की शर्तों के अनुसार भारत में प्रदत्त मूल्य के रूप में चीन में प्रचलित सामान्य मूल्य के अनुमान उपलब्ध कराए गए थे। जांच की शुरुआत के पश्चात प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों को सूचित किया गया कि प्राधिकारी द्वारा, यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा (7) एवं (8) के आलोक में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने के याचिकाकर्ता के दावे की जांच प्रस्तावित है। अतः चीन जन-गण के संबद्ध वस्तुओं से संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया कि वे अनुबंध-1 के पैरा-8 में उल्लिखित आवश्यक जानकारी/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जा सके कि सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया जा सके, जो उक्त पैराग्राफ में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।

- (iv) उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा चीन के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/विनिर्माताओं एवं संबद्ध देश के भारत स्थित दूतावास को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराई गई;
1. सिक्सी सेन्ताई केमिकल फाइबर कंपनी लि.
 2. जिजियांग सीफू केमिकल फाइबर कंपनी लि.
 3. डब्ल्यू डब्ल्यू टेक्सटाइल कं. लि.
 4. हेंगजाऊ हुआजिन टेक्सटाइल कं. लि.
 5. जिजियांग सनशाइनिंग टेक्सटाइल कं. लि.
 6. टोंगकुन ग्रुप जेजियांग हेंगशेंग केमिकल फाइबर कंपनी लि.
 7. हेंगजाऊ जोंगली केमिकल फाइबर कंपनी लि.
- (v) जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में चीन के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।
- (vi) नियम 6(2) के अनुसरण में सम्बद्ध देश, चीन के दूतावास को जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया और उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली के उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया। निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की एक-एक प्रति भी उन्हें भिजवाई गई।

(vii) नियम 6(4) के अनुसरण में सम्बद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को आवश्यक जानकारी हेतु एक प्रश्नावली भिजवाई गई:

1. ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन, मुंबई
2. साउथ गुजरात टेक्सचराइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन, सूरत
3. सनटेक्स इंडिया
4. गैलेक्सी टेक्सटाइल्स
5. हारमनी यार्न्स प्रा.लि.
6. एवीएम एक्सपोर्ट्स
7. गर्ग टेक्स-ओ-फैब लि.
8. बोधारा षोलिफैब प्रा.लि.
9. सिलवासा इंडस्ट्रीज लि.
10. बीकेलॉन सिंथेटिक्स लि.
11. आलोक इंडस्ट्रीज लि.
12. बाजारी फिलामेंट्स प्रा.लि.
13. सिद्धवन यार्न्स लि.
14. क्रिम्पलॉन यार्न्स
15. यूनीटेक्स टेक्सचराइजर्स
16. यूनीफाई टेक्सचराइजर्स
17. घूमटेक्स (इंडिया) प्रा. लि.
18. मेहराटेक्स इंडिया प्रा. लि.
19. एसआरवी पॉलीटेक्स प्रा.लि.
20. सिनफैब सेल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.

(viii) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में मै. ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन, मुंबई तथा फेडरेशन ऑफ आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री (एफआईएसडब्ल्यूआई) ने अपना-अपना उत्तर प्रस्तुत किया ।

(ix) अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को भी याचिका की गैर-गोपनीय प्रति उपलब्ध कराई गई ।

(x) प्राधिकारी द्वारा, विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गैर-गोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा गया और नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा निरीक्षण हेतु इसे उपलब्ध रखा गया ।

(xi) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए

पर्याप्त होगा, सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर उत्पादन की अनुकूलतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत की गणना करने के लिए लागत की जांच की गई ।

(xii) इस अधिसूचना में **** एक हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी प्रदर्शित करता है, जिसे प्राधिकारी द्वारा उसके गुणों के आधार पर नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना गया है ।

(xiii) यह जांच दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 30 जून, 2005 तक (15 माह) अर्थात् जांच अवधि (पीओआई) हेतु की गई । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2001-02, 2002-03, 2003-04 की अवधि तथा जांच अवधि को शामिल किया गया ।

ख. विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु एवं घरेलू उद्योग

5. विचाराधीन उत्पाद

इस याचिका में विचाराधीन उत्पाद पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न है, जिसे सामान्यतः पीओवाई कहा जाता है । यह भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के तहत सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 5402.42 के अंतर्गत आता है । यह पोलिएस्टर का धागा होता है और एक मध्यवर्ती पदार्थ है, जिसे कपड़े के रूप में बुनाई अथवा निटिंग के योग्य बनाने के लिए इसकी आगे प्रोसेसिंग उदाहरणार्थ टैक्सचरिंग अथवा ट्विस्टिंग की जाती है ।

आयातकों तथा प्रयोक्ताओं द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा वह डेनियर विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके लिए पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित है, क्योंकि इसका उत्पादन कई प्रकार से किया जाता है । याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि याचिका में विनिर्दिष्ट संबद्ध वस्तुओं में सभी प्रकार के डेनियर कवर किए गए हैं और याचिका में संबद्ध वस्तुओं के डेनियर विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । अतः उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आयातकों तथा प्रयोक्ताओं का विचार निराधार है और गुण रहित है । प्राधिकारी द्वारा इस मामले पर व्यक्त अभिमतों पर विचार किया गया और उनका यह विचार है कि विचाराधीन उत्पाद में ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका दावा आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा किया गया है । अतः प्राधिकारी के अनुसार आयातकों के तर्क का कोई आधार नहीं है ।

6. समान वस्तु

पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार समान वस्तु की परिभाषा निम्नलिखित है :-

"वह वस्तु जो सभी प्रकार से जांच के अधीन वस्तु के समान है अथवा उस जैसी है, जिसका पाटन भारत में किया जा रहा है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में अन्य कोई वस्तु, जो यद्यपि सभी प्रकार से समान नहीं है, तथापि उसकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तु से बहुत अधिक मेल खाती हैं ।"

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जिनका पाटन भारत में किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं । पाटित आयातों और घरेलू तौर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यो अथवा अंतिम उपयोग में कोई भिन्नता नहीं है ।

प्राधिकारी ने पाया है कि न तो किसी निर्यातक और न ही किसी संबद्ध पक्ष ने इस बात पर विवाद किया है कि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई भिन्नता है । प्राधिकारी ने यह देखा है कि आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग प्रयोक्ता उद्योग द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, अतः वे पाटनरोधी नियमावली के तहत "समान वस्तुएं" हैं । अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तुओं को सम्बद्ध देशों से आयात की जा रही सम्बद्ध वस्तुओं के "समान वस्तुएं" माना जा रहा है ।

7. घरेलू उद्योग

नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित है :-

(ख) "घरेलू उद्योग" से तात्पर्य समस्त घरेलू उत्पादकों से है, जो समान वस्तु के विनिर्माण तथा उससे संबंधित किसी गतिविधि में संलग्न हैं अथवा वे जिनका समान वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, सिवाय उस स्थिति के, जब ऐसे उत्पादक कथित रूप से पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों, अथवा स्वयं उसके आयातक हों, उस मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा ।"

याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादक शामिल हैं :-

- i. अफीस इंडस्ट्रीज लि.
- ii. मै. अपोलो फाइबर्स लि.
- iii. सेंट्रल इंडिया पॉलिएस्टर्स लि.
- iv. सेंचुरी एन्का लि.
- v. फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज लि.
- vi. गार्डन सिल्क मिल्स लि.
- vii. इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लि.
- viii. जेबीएफ लि., मै. मॉर्डन पेट्रोफिल्स लि.
- ix. मॉर्डन पेट्रोफाइल्स लि.
- x. नकोड़ा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लि.
- xi. रेक्रॉन सिंथेटिक्स लि.
- xii. वेलस्पन सिन्टेक्स लि.

प्राधिकारी ने पाया है कि याचिका को निम्नलिखित उत्पादकों ने भी समर्थन दिया है :-

- क. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
- ख. सांघी पॉलिएस्टर्स लि.
- ग. नोवा पेट्रोकेमिकल्स लि.
- घ. गोकुलानन्द पेट्रोफाइबर्स
- ङ. राजवी पेट्रोकेम (प्रा.) लि.

प्राधिकारी ने पाया है कि उपर्युक्त उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, अतः वे ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 2(ख) के भीतर घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राधिकारी ने यह भी निर्धारण किया है कि उपर्युक्त उत्पादक नियम 5(3) की शर्तों के अनुसार याचिका दायर करने संबंधी मानदंड की पूर्ति करते हैं।

प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि हितबद्ध पक्षों अथवा निर्यातकों ने ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के मानदंड को पूरा नहीं करते जैसा कि नियमावली के तहत निर्धारित है। एक हितबद्ध पक्ष ने दावा किया है कि मैसर्स वेलस्पन के आयातों का विश्लेषण उनके स्वयं के उत्पादन की तुलना में किया जाए। प्राधिकारी ने

यह पाया है कि यद्यपि हितबद्ध पक्षों ने कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया है, तथापि यह देखा गया कि चीन जन.गण. से वेलस्पन द्वारा आयात उनके स्वयं के उत्पादन का लगभग 0.1% है, जो बहुत कम मात्रा है, जिसे मेसर्स वेलस्पन को घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने के प्रयोजनार्थ नगण्य माना जा सकता है ।

ग. सामान्य मूल्य

8. याचिकाकर्ता के दावे

क. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सम्बद्ध देश अर्थात् चीन पाटनरोधी नियमावली के तहत गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । अतः चीन के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

ख. पैराग्राफ 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के घरेलू विक्रय मूल्यों अथवा बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में संरचित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश के निर्यात मूल्य में से, किसी भी आधार पर किया जाना अपेक्षित है । तथापि यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता हो, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी भी उचित आधार पर किया जा सकता है, जिसमें समान उत्पाद हेतु लाभ की समुचित गुंजाइश सहित अदा अथवा भुगतान योग्य वास्तविक मूल्य शामिल हैं ।

ग. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रथम विकल्प के रूप में किसी तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था देश का चयन किया जाना अपेक्षित है । जांच की शुरुआत के समय प्रस्ताव किया गया है कि समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में ताइवान को चुना जाए ।

घ. हितबद्ध पक्षों ने प्राधिकारी के समक्ष अपने आवेदन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ताइवान को सहोदर देश के रूप में क्यों व कैसे चुना जाए और याचिकाकर्ता द्वारा चीन हेतु यथा निर्धारित सामान्य मूल्य स्वीकार्य क्यों नहीं है । अतः घरेलू उद्योग द्वारा यह

अनुरोध किया गया कि हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए आधारहीन दावों पर विचार न किया जाए ।

9. हितबद्ध देशों के दावे

- क. ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन ने कहा है कि चीन हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण में ताइवान को सहोदर देश के रूप में चुनना सही नहीं है ।
- ख. एफआईएसडब्ल्यूआई ने दावा किया है कि ताइवान में संरचित सामान्य मूल्य के आधार पर चीन हेतु, सामान्य मूल्य का निर्धारण यथार्थ से परे है ।

10. प्राधिकारी द्वारा जांच

- i. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांचों में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाता है ।
- ii. प्राधिकारी ने पाया है कि चीन के उत्पादकों में से किसी ने भी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर नहीं भेजे हैं । चीन के उत्पादकों में से किसी ने भी यह दावा नहीं किया है कि उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाए । अतः प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसरण में किया गया । चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है :-
 - (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर, अथवा
 - (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संरचित मूल्य, अथवा
 - (ग) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत
 - (घ) यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता हो, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य समुचित आधार पर भी किया जा सकता है, जिसमें समान वस्तु हेतु लाभ की

समुचित गुजाइश के समायोजन सहित भारत में प्रदत्त अथवा भुगतान योग्य मूल्य शामिल है ।

- iii. याचिकाकर्ता द्वारा ताइवान को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में चुनने का सुझाव दिया गया था । प्राधिकारी ने भी ताइवान को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे उचित देश के रूप में प्रस्तावित किया था और जांच की शुरुआत के समय सभी हितबद्ध पक्षों से टिप्पणियां एवं जानकारी आमंत्रित की थी । तथापि, ताइवान में प्रचलित कीमतों व लागतों के बारे में किसी उत्तर अथवा जानकारी के अभाव में प्राधिकारी के लिए इस समय भारतीय पाटनरोधी, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में यथा उल्लिखित उपर्युक्त (क) से (ग) में दर्शाई गई पद्धतियों से चीन हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है । ऐसी परिस्थिति में इस प्रारंभिक जांच परिणाम में प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के पास नियमावली में यथा निर्धारित तरीके से विधिवत रूप से समायोजन सहित, भारत में प्रदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर चीन हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है । भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य ज्ञात करते समय प्राधिकारी द्वारा कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया, वहीं भारत में प्रचलित उपभोग मानदंडों, परिवर्तन लागत तथा अन्य लागतों पर विचार किया गया । भारत में भुगतान योग्य कीमत की गणना करते समय उत्पादन लागत में समुचित मुनाफा भी जोड़ दिया गया है । इस प्रकार, इस प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य **** रूपए प्रति मी. टन निर्धारित किया गया है ।

घ. निर्यात मूल्य

11. जांच की शुरुआत हेतु प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता ने निर्यात मूल्य की गणना डीजीसीआईएंड एस के आयात आंकड़ों के आधार पर की थी । प्राधिकारी द्वारा भी डीजीसीआईएंड एस से आयात आंकड़े प्राप्त किए गए और यह पाया गया कि सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 5402.42 (जो विचाराधीन उत्पाद हेतु निर्धारित कोड है) के तहत आयातों की मात्रा तथा मूल्य वही है, जो याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया था । डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ निर्यात मूल्य 43053 रूपए प्रति मी.टन (958 अमरीकी डॉलर प्रति मी.टन) है । समुद्री बीमा, कमीशन, समुद्री

मालभाड़, बैंक प्रभार तथा पत्तन व्यय के कारण हुए मूल्य समायोजन पर विचार करने के बाद निवल निर्यात मूल्य *** रूपए प्रति मी. टन (***) अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन) बनता है ।

ड पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत के बीच निष्पक्ष तुलना के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य व निर्यात कीमत, दोनों का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर किया गया । सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत दोनों एक ही अवधि से संबंधित हैं । दोनों कीमतें करों से मुक्त हैं । अतः प्राधिकारी का विचार है कि की गई तुलना निष्पक्ष तुलना है । ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निवल निर्यात कीमत पर विचार करने के बाद पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है जो *** रूपए प्रति मी. टन, (***) अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन) है, जो निवल निर्यात कीमत का 38% बनता है ।

च. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

13. घरेलू उद्योग का अभिमत

घरेलू उद्योग ने कहा है कि आधार वर्ष 01 अप्रैल- 02 मार्च की तुलना में जांच अवधि के दौरान चीन से आयात का हिस्सा न केवल कुल आयात के मुकाबले बढ़ा है, अपितु यह कुल मांग व कुल उत्पादन के मुकाबले भी कई गुना बढ़ा है ।

चीन से पाटित आयातों का घरेलू कीमतों पर प्रभाव पड़ा और कीमत में कटौती तथा जांच अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से कम कीमत पर बिक्री हुई । बाजार का हिस्सा, क्षमता उपयोग, लाभकारिता, निवेश पर लाभ, नकदी प्रवाह, वृद्धि आदि क्षति जांच अवधि के दौरान कम हुई । घरेलू उद्योग की बिक्रियां बढ़ गई हैं तथापि, बिक्रियों में वृद्धि, मांग में वृद्धि की तुलना में कम है । चीन से पाटन का मार्जिन भी जांच अवधि के दौरान पर्याप्त है जिससे मालूम होता है कि घरेलू उद्योग को अपनी संबद्ध वस्तु के निपटान में कठिनाई आ रही है ।

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

आयातकों और प्रयोक्ता एसोसिएशनों के विचार संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं :-

- (i) पीओवाई की कीमतें अन्य देशों के लिए भी कम हो गई हैं ।

- (ii) पीओवाई की मांग घरेलू उत्पादन का तुलना में वर्ष 2001-02 से अधिक हैं और देशी उद्योग कमी उत्पन्न करके पर्याप्त रूप से लाभान्वित हुआ है ।
- (iii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पर्याप्त गिरावट आई है ।
- (iv) घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा मांग में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप बढ़ी है ।
- (v) रोजगार और वेतनों के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है ।
- (vi) घरेलू उत्पादकों की सतुलन शीटो के अनुसार उन्हें घाटा नहीं हो रहा है और अधिकांश कंपनियां लाभ अर्जित करने वाली उद्योग हैं ।
- (vii) जांच अवधि के दौरान जाचिकाकर्तों की माल सूचियां पिछले वर्षों की तुलना में वस्तुतः कम हैं ।
- (viii) कच्ची सामग्री की कीमतें कम हैं और चीन की तुलना में भारत में कीमतें अधिक हैं । जहां कि कच्ची सामग्री की कीमतें अधिक है और पीओवाई की कीमतें कम हैं ।
- (ix) लगभग सभी कंपनियां अपनी क्षमताएं बढ़ा रही हैं जिससे मालूम होता है कि पीओवाई के आयात से घरेलू उद्योग बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है ।

15. प्राधिकारी द्वारा जांच

क्षति मानदंडों का विश्लेषण जैसा कि नियमों के अंतर्गत परिकल्पित है, निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है :-

- (i) **आयातों की मात्रा:** प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के आधार पर संबद्ध देश से आयातों की मात्रा की जांच की है जैसा कि डीजीसीआईएंड एस द्वारा प्रकाशित सरकारी आंकड़ों में दर्शाया गया है । यह मालूम हुआ है कि कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा 2001-02 में 2% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 79% हो गया है । सही मात्रा में संबद्ध देश से आयात जांच अवधि के दौरान बढ़कर आधार वर्ष 2001-02 में हुए आयातों का लगभग 25 गुणा के स्तर पर पहुंच गए हैं जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
चीन से आयात (मी.ट.)	1461	1811	8693	46215	36972
कुल आयात (मी.ट.)	59044	70705	33265	58382	46706
% हिस्सा	2%	3%	26%	79%	79%

- (ii) आयातों का बाजार हिस्सा: प्राधिकारी को यह मालूम हुआ कि भारत में कुल मांग की तुलना में चीन से आयात 2001-02 के दौरान 0.22% के कम स्तर से बढ़कर जांच अवधि में 4.65% हो गया है। वर्ष दर वर्ष प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति निम्न प्रकार है :-

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
चीन से आयात (मी.ट.)	1461	1811	8693	46215	36972
कुल मांग (मी.ट.)	678812	727431	730597	994315	795452
% हिस्सा	0.22%	0.25%	1.19%	4.65%	4.65%

- (iii) संबद्ध देश से घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में चीन से आयात वर्ष 2001-02 में 0.37% के स्तर से बढ़कर जांच अवधि के दौरान अत्यधिक बढ़े हैं।

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
चीन से आयात (मी.ट.)	1461	1811	8693	46215	36972
उत्पादन (मी.टन)	399348	421371	439429	629367	503493
% हिस्सा	0.37%	0.43%	1.98%	7.34%	7.34%

इस प्रकार चीन से आयात केवल वास्तविक रूप से ही नहीं बढ़े हैं बल्कि भारत में कुल आयातों, बाजार मांग और घरेलू उत्पादन के हिस्से के रूप में भी बढ़े हैं।

- (iv) **संविदाएं प्राप्त न होने के संबंध में साक्ष्य:** हालांकि संविदाएं प्राप्त न होने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है परंतु यह स्पष्ट है कि बाजार के हिस्से का घाटा और पाटित आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि का यह संकेत है कि घरेलू उद्योग बिक्री न होने के कारण घाटे में जा रहा है। प्राधिकारी को यह मालूम होता है कि जांच अवधि के दौरान 43053 रुपए/मी.टन (सीआईएफ मूल्य) की कम कीमत पर 46,215 मी.टन का पाटित आयात स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि घरेलू उद्योग चीन से पाटित आयातों के कारण बिक्रियां खो चुका है।
- (v) **घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा :** प्राधिकारी को यह मालूम होता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और भारत में सबद्ध वस्तु की मांग में संबद्ध देशों से आयात निम्न प्रकार रहे हैं :-

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
घरेलू बिक्रियां	619769	656726	697332	935933	748746
कुल मांग (मी.टन)	678812	727431	730597	994315	795452
% हिस्सा	91.30%	90.28%	95.45%	94.13%	94.13%

प्राधिकारी को मालूम हुआ कि घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 2003-04 में 95.45% से घटकर जांच अवधि के दौरान 94.13% हो गया था। यह भी नोट किया गया है कि उसी अवधि में मांग 36% बढ़ी है। इससे मालूम होता है कि घरेलू उद्योग मांग में कोई बढ़ोत्तरी प्राप्त नहीं कर सका और यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से के संबंध में क्षति हुई है। यह भी नोट किया गया है कि उसी अवधि में चीन से आयात 5 गुणा से अधिक बढ़े हैं यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से के साथ-साथ बाजार में वृद्धि को संबद्ध देश से आयातों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ले लिया गया है।

- (vi) **उत्पादन और क्षमता उपयोग :** घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार रहा है :-

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
क्षमता (मी.ट.)	446000	497000	521000	769000	615000
उत्पादन (मी.ट.)	399348	421371	439429	629367	503493
क्षमता उपयोग %	90%	85%	84%	82%	82%

प्राधिकारी को यह मालूम होता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्ष 2001-02 में 90% से घटकर जांच अवधि के दौरान 82% रह गया है। इस प्रकार क्षमता उपयोग में 8% की कमी आई है और दूसरी ओर क्षति जांच अवधि में आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- (vii) **बिक्री की मात्रा और मूल्य:** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में कम है जिससे स्पष्ट रूप से यह मालूम होता है कि घरेलू उद्योग को अपनी बिक्रियों के संबंध में क्षति हुई है।

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
बिक्रियां (मी.ट.)	320299	328665	339900	512145	409716
बिक्री का मूल्य (रुपए-लाख)-सूची	100	114	128	210	168

- (viii) **माल सूचियाँ :** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की माल सूचियों का स्तर जांच अवधि में नीचे चला गया है परंतु बिक्रियों में वृद्धि घाटे पर हुई।

- (ix) **कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री :** प्राधिकारी ने पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली की तुलना की पद्धति का प्रयोग किया है। विचार की गई बिक्री वसूली का मूल्य डिकाउंटों, कमीशन और प्रहस्तन/भाड़ा प्रभारों की निवल राशि है। घरेलू कीमत की आयातित उत्पाद की कीमत के साथ तुलना इस प्रकार उसी स्तर पर है। इसी प्रकार कम मूल्य पर बिक्री के स्तर की गणना गैर क्षति कारक कीमत (एनआईपी) के साथ चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ करने के आधार पर की गई है। प्राधिकारी को यह मालूम होता है कि चीन से

पाटित आयातों के कारण पर्याप्त रूप से कीमत कटौती के साथ-साथ कम कीमत पर बिक्री हुई है ।

- (x) **घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से कीमत कटौती का स्तर पाटित आयातों के कारण पर्याप्त रहा है । इसके अतिरिक्त, कम कीमत पर बिक्री भी स्पष्ट है क्योंकि चीन से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत से पर्याप्त रूप से बहुत कम है । चीन से आयातों की पहुंच कीमत/मी.टन वर्ष 2002-03 की तुलना में जांच अवधि के दौरान अत्यधिक कम रही है । जबकि उसी समय कच्ची सामग्री की लागत कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हैं । इससे स्पष्ट रूप से यह मालूम होता है कि घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव उससे बहुत ही अधिक है जो आंकड़ों के साधारण विश्लेषण से मालूम होता है । घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों के संबंध में यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि की तुलना में उनमें वृद्धि हुई है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में वृद्धि लागतों में वृद्धि की तुलना में बहुत कम हुई है जिससे स्पष्ट रूप से यह मालूम होता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें चीन से पाटित आयातों के कारण मंदी रही हैं । घरेलू उद्योग की दबी हुई कीमतों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान घाटा हुआ है ।

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)
इस देश से पहुंच मूल्य (सूचीबद्ध)	100.00	111.17	86.27	91.92
घरेलू बिक्री कीमत रू./मी.ट.	100.00	111.03	120.33	131.51
लागत रू./मी.टन (सूचीबद्ध)	100.00	108.94	114.70	134.31

- (xi) **पाटन मार्जिन की मात्रा :** प्राधिकारी को यह मालूम हुआ है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन मार्जिन की मात्रा अत्यधिक रही है ।

- (xii) **रोजगार और वेतन:** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई है और अनेक व्यक्तियों को रोजगार दिया है। तदनुसार अनेक कर्मचारी और उनको दिए गए वेतन क्षति जांच अवधि के दौरान बढ़े हैं।
- (xiii) **उत्पादकता:** प्राधिकारी को यह मालूम होता है कि जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता आधार वर्ष 2001-02 की तुलना में बढ़ी है। इसलिए यह नोट किया जाता है कि उत्पादकता का घाटा घरेलू उद्योग को क्षति होने का कोई कारण नहीं है।
- (xiv) **लाभकारिता :** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग चीन से पाटन के कारण जांच अवधि के दौरान लाभ का वांछित स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2003-2004 में लाभ का स्तर 5.74% प्राप्त किया है तथापि, जो जांच अवधि के दौरान एक नकारात्मक स्तर (0.99%) पर आ गया था, जिसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :-

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
लाभ/घाटा (रु./इकाई)	****	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	296	621	-118	-118
बिक्री कर पर % लाभ/घाटा	1.11%	2.97%	5.74%	-0.99%	-0.99%

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में घरेलू उद्योग को चीन की पाटित कीमतों के अनुरूप कीमतों में कमी करने का सहारा लेना पड़ा था।

- (xv) **निवेश पर लाभ (नियोजित पूंजी):** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियोजित पूंजी पर लाभ भी उसी प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ता है जैसे कि लाभकारी का/घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान अपने निवेश पर कोई लाभ अर्जित

नहीं कर सका । जबकि इसने पिछले वर्ष 2003-04 में 8% लाभ अर्जित किया ।

- (xvi) नकदी प्रवाहों पर वास्तविक और संभावित प्रतिकूल प्रभाव : प्राधिकारी को यह मालूम होगा कि नकद लाभ/नकदी प्रवाह में भी वही प्रवृत्ति रही जो उस अवधि के दौरान लाभकारिता की थी और यह लगभग आधार वर्ष 2001-02 में नकद लाभ का लगभग दो तिहाई कम हो गई थी ।

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
नकद लाभ/नकदी प्रवाह/मी.ट.	****	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	137	178	68	68

- (xvii) वृद्धि : प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा बढ़ गई है तब भी जांच अवधि के दौरान बिक्री की मात्रा में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम है और उसी अवधि के दौरान कुल मांग में वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजारों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है ।

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि (%)	-	4.65	6.24	33.39	6.71
घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि (प्रत्येक वर्ष) (%)	-	-1.17	5.46	-1.35	-1.35
मांग में वृद्धि (प्रत्येक वर्ष) (%)	-	5.89	0.74	35.22	8.18

- (xviii) पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता: प्राधिकारी को यह मालूम होगा कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर घरेलू उद्योग को हुए घाटों को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकारात्मक लाभ तथा लाभों में गिरावट की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

घ. क्षति के संबंध में निष्कर्ष:

16. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं :-

- (क) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में अपर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कुल मांग और भारत में घरेलू उत्पादन के संबंध में भी थी ।
- (ख) घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा कम हो गया है जबकि आयातों में वृद्धि हुई है ।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की लाभकारिता जांच अवधि के दौरान नकारात्मक हो गई है तथा निवेश पर लाभ और नकदी प्रवाह जांच अवधि में घटकर मामूली स्तर पर आ गए हैं ।
- (घ) घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम हो गया है ।
- (ङ) पर्याप्त और गंभीर कीमत कटौती के साथ-साथ कम कीमत पर बिक्री हुई है ।
- (च) संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन पर्याप्त है ।

इसलिए प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, जैसे कि नियमों के अंतर्गत परिकल्पना की गई थी ।

ज. कारणात्मक संबंध तथा अन्य कारक

17. पाटित आयातों का प्रभाव:

वर्ष 2001-02 और जांच अवधि के बीच संबद्ध वस्तु के कुल आयात के प्रतिशत के रूप में संबद्ध देश से पाटित आयात पर्याप्त रूप से 2% से बढ़कर 79% हो गए । कुल मांग की तुलना में चीन से आयातों के हिस्से का प्रतिशत जांच अवधि के दौरान बढ़ रहा है । यह वृद्धि 2001-02 में 0.22% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 4.65% हो गई है । कीमत प्रभाव की जांच करते समय कि क्या पाटित आयातों से भारत में संबद्ध वस्तु की कीमत में पर्याप्त कमी हुई है । प्राधिकारी को यह मालूम होगा कि चीन से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में पर्याप्त रूप से कटौती

हुई । यह मालूम होता है कि कीमत कटौती और आयातों के पहुंच मूल्य के कीमत निर्धारण व्यवहार से घरेलू उद्योग को अलाभकारी स्तर पर घरेलू कीमतें बनाए रखने और यहां तक कि उत्पादन की लागत से कम रखने के लिए बाध्य होना पड़ा जिससे घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उत्पादन लागत में पूरी वृद्धि वसूल करने के लिए बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका और जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा उठाना पड़ा । कीमत कटौती के साथ-साथ कम कीमतों से घरेलू उद्योग की लाभकारिता कम हो गई । घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान चीन से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

18. अन्य कारकों का प्रभाव:

- (क) **व्यापार प्रतिबद्धात्मक प्रथा और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा:** प्राधिकारी को भारतीय उत्पादकों और अन्य प्रतिस्पर्धी उद्योगों द्वारा अपनाई गई कोई व्यापार प्रतिबद्धात्मक प्रथाएं मालूम नहीं हुई हैं । घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू मांग के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता के संबंध में यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आपूर्तिकर्ताओं पर घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा जिसे घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने हेतु अप्रयुक्त क्षमता है यदि एक उचित कीमत पर बाजार में प्रतिस्पर्धा हो ।
- (ख) **मांग की कमी अथवा खपत के तरीके में परिवर्तन :** यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन अवधि के दौरान मांग में कोई कमी नहीं हुई है इसके विपरीत जांच अवधि के दौरान समग्र मांग बढ़ी है । इसलिए, मांग में संभावित कमी कोई कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती ।
- (ग) **प्रौद्योगिकी :** किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि प्रौद्योगिकी घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारक है ।
- (घ) **निर्यात कार्य निष्पादन:** घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के साथ-साथ पिछले वर्षों में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है । प्राधिकारी नोट

करते हैं कि घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है । घरेलू और निर्यात बिक्रियों को लाभकारिता की क्षति की जांच के लिए अलग किया गया है । इसलिए निर्यात के कारण हुई क्षति (यदि कोई हो) को घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के कारण हुई नहीं माना गया है । घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

	2001-02	2002-03	2003-04	जांच अवधि (15 महीने)	जांच अवधि वार्षिक
निर्यात (मी.ट.)	9879	13115	17862	24260	19408
निर्यात (लाख रु.)	****	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	145	197	305	244

(ङ) **उत्पादकता :** घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आधार वर्ष 2001-02 की तुलना में जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है । इसके अनुसार उत्पादकता घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं हो सकती ।

च. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे:

19. प्राधिकारी यह मानते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित करने की सुविधा हो सके ।
20. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के स्तर प्रभावित हो सकते हैं और उसके फलस्वरूप इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है तथापि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा इन पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों से पाटन प्रथाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ समाप्त होंगे और घरेलू उद्योग का पतन रुकेगा तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की व्यापक पसंद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी ।

छ. निष्कर्ष:

21. प्राधिकारी पूर्वोक्त पर कार्यवाही और विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :-

- (क) संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत को उनके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया गया है ।
- (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।
- (ग) घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से निर्यातित अथवा वहां से मूल की संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों से हुई है ।
- (घ) इस प्रकार प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित अथवा वहां के मूल की सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय-54 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाए ।

ज. सिफारिशें:

22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के पहलु के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था । निर्धारित नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के बीच कारणात्मक संबंध : पाटन और क्षति की प्रारंभिक जांच शुरू करके जांच पूरी करने को ध्यान में रखते हुए और ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के साथ-साथ संबद्ध देश के विरुद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन अनंतिम रूप से सिद्ध करके प्राधिकारी का यह मत है कि अंतरिम शुल्क की जांच पूरी किए जाने तक पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए लगाया जाना आवश्यक है ।

23. इसलिए प्राधिकारी निम्नलिखित रूप में और ढंग से संबद्ध देश की संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

24. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति के मार्जिन से कम के समान अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोका जा सके । तदनुसार, निम्नलिखित तालिका 9 में उल्लिखित राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को चीन के मूल के अथवा वहां से आयातित सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 के अंतर्गत आने वाले पार्शियली ओरियटीज यार्न के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना से लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ।

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	बिनिदि टा	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402.42	पार्शियली ओरिएंटेड यार्न-सभी किस्में	कोई	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	486	मी.ट.	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	-वही-	कोई	चीन जन.गण.	कोई	कोई	486	मी.ट.	अम.डॉ.

(ड) आगे की प्रक्रिया :

25. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- (क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और उस पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा ।
- (ख) निर्यातक, आयातक, याचिकाकर्ता और ज्ञात अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने विचार इन प्रारंभिक जांच परिणामों की तिथि से चालीस दिन (40) के भीतर ज्ञात करा सकते हैं ।
- (ग) प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे जांच करेंगे ।
- (घ) प्राधिकारी मौखिक निवेदनों, जिनके लिए सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से तारीख और समय पर सूचित किया जाएगा, के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करेंगे ।
- (ङ) प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने से पहले आवश्यक तथ्यों को भी प्रकट करेंगे ।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2006

Preliminary Findings

Subject :— Anti dumping investigation concerning imports of Partially Oriented Yarn (POY) from China PR.

No. 14/10/2005-DGAD :—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof:

2. Whereas M/s Association of Synthetic Fibre Industries (hereinafter referred to as the Applicant) on behalf of domestic producers namely

M/s Arfees Industries Ltd., M/s Appollo Fibres Ltd., M/s Central India Polyesters Ltd., M/s Century Enka Ltd., M/s Filatex Industries Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd., M/s Indo Rama Synthetics (India) Ltd., M/s JBF Ltd., M/s Modern Petrofils Ltd., M/s Nakoda Textiles Industries Ltd., M/s Recron Synthetics Ltd. and M/s Welspun Syntex Ltd, filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act and the AD Rules, alleging dumping of Partially Oriented Yarn (herein after referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (herein after referred to as subject country) and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

3. And whereas the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 13th December 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with the Rule 6 of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigations by the Authority.
- i) The Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of dumping application made by the Applicant before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;
 - ii) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers/users and to the applicant and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the publication of initiation notification in accordance with the Rule 6(2):
 - iii) A questionnaire for according market economy treatment was forwarded to all the known exporters and the Embassy of the Peoples' Republic of China. For the purpose of initiation, normal value had been based on the basis of constructed normal value in Taiwan as appropriate estimate of normal value. In an alternate to the price from a market economy third

country to India, applicant had also provided estimates of normal value in China as price payable in India in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. Subsequent to initiation, the Authority informed the known exporters that the Authority proposed to examine the claim of the applicant of treating China as non-market economy in the light of paras (7) & (8) of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules as amended. The concerned exporters / producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information / sufficient evidence as mentioned in paragraph 8 of Annexure-I to enable the Designated Authority to consider whether market economy treatment could be granted to cooperating exporters / producers who could demonstrate that they satisfied the criteria stipulated in the said paragraph.

- iv) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the application to the following known exporters/manufacturers from China and Embassy of subject country in India;

1. Cixi Santai Chemical Fibre Co., Ltd.
2. Zhejiang Cifu Chemical Fiber Co., Ltd.
3. W.W Textile Co., Ltd.
4. Hangzhou Huaxin Textile Co., Ltd.
5. Xinxiang Sunshining Textiles Co., Ltd.
6. Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fibre Co., Ltd.
7. Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd.

- v) In response to the initiation notification none of the exporter/producer from China responded to the questionnaire.

- vi) The Embassy of the subject country, China, was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, application and questionnaire sent to the exporters was also sent to them;

- vii) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):

1. All India Texturisers Association, Mumbai
2. South Gujarat Texturisers Welfare Association, Surat
3. Suntex India
4. Galaxy Textiles

5. Harmony Yarns PVT. Ltd.
6. AVM Exports
7. Garg Tex-O-Fab Ltd.
8. Boghara Polyfab Private Ltd.
9. Silvassa Industries Ltd.
10. Beekaylon Synthetics Ltd.
11. Alok Industries Ltd.
12. Bajari Filaments P Ltd.
13. Sidhvan Yarns Ltd.
14. Crimpon Yarns
15. Uni Tex Texturisers
16. Unify Texturisers
17. Ghoomtex (India) Pvt Ltd.
18. Mehratex India P Ltd.
19. SRV Polytex Pvt. Ltd.
20. Synfab Sales and Industries Ltd.

- viii) In response to the above notification M/s All India Texturisers' Association, Mumbai and Federation of Indian Art Silk Weaving Industry (FIASWI) have filed their submissions.
- ix) A copy of the non-confidential application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- x) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- xi) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xii) **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.
- xiii) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2004 to 30th June 2005 (15 months) i.e. the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period 2001-02, 2002-03, 2003-04 and the POI.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, LIKE ARTICLE AND DOMESTIC INDUSTRY:

5. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present application is Partially Oriented Yarn generally known as POY. It falls under the Custom Tariff Heading 5402.42 under the Indian Custom Tariff Classification. It is yarn of polyester and is an intermediate, which is subject to further processing, for example, texturing or draw twisting, to make it suitable for weaving or knitting into fabrics.

It has been contended by the importers and users that the applicant has not specified the denier for which the anti-dumping duty is sought as the same are produced in a wide range. It has been claimed by the Applicant that the subject goods specified in the application covers all types of denier and there is no need that the denier of the subject goods is to be specified in the application. They have therefore contended that the submission of the importers and the users is baseless and devoid of any merit. The Authority has considered the views expressed on the issue and is of the view that the product under consideration does not suffer from any infirmity as claimed by the importers/users. Therefore, the Authority does not find any merit in the argument of the importers.

6. LIKE ARTICLE

Rule 2(d) of AD Rules defines Like Article as

"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."

The applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject good.

The Authority notes that neither the exporters nor the interested parties have disputed the fact that there is any

difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the domestic industry. The Authority observes that the imported goods are used by the user industry interchangeably with the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and produced by the subject countries being technically and commercially substitutable, are 'like articles' under the Anti Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'Like Articles' to the subject goods being imported from the subject country.

7. DOMESTIC INDUSTRY

Rule 2(b) defines domestic industry as under:-

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry:

The application has been filed by M/s Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi on behalf of domestic industry comprising of the following producers of subject goods in India:

- I. Arfees Industries Ltd.
- II. Apollo Fibres Ltd.
- III. Central India Polyesters Ltd.
- IV. Century Enka Ltd.
- V. Filatex Industries Ltd.
- VI. Garden Silk Mills Ltd.
- VII. Indo Rama Synthetics (India) Ltd
- VIII. JBF Ltd.
- IX. Modern Petrofils Ltd.
- X. Nakoda Textiles Industries Ltd.
- XI. Recron Synthetics Limited
- XII. Welspun Syntex Ltd.

The Authority notes that the application has also been supported by the following producers:

- a. Reliance industries Ltd.
- b. Sanghi Polyesters Ltd.
- c. Nova Petrochemicals Ltd.
- d. Gokulanand Petrofibres
- e. Rajvi Petrochem (P) Ltd.

The Authority notes that the collective production of the aforesaid producers constitutes a major proportion of the total domestic production of the like article and therefore they represent the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules supra. The Authority also determines that aforesaid producers satisfy the criteria of standing to file the application on behalf of the domestic industry in terms of Rule 5(3).

The Authority also notes that there are no arguments from the interested parties or the exporters that the applicants do not meet the criteria of standing as laid down under the Rules. One of the interested parties has claimed that the analysis of imports from M/s Welspun is to be made in comparison to their own production. While the Authority notes that no convincing reasons have been advanced by the interested parties, it is observed that the imports by Welspun from China PR are approximately 0.1% of its own production, which is a miniscule quantity and can be ignored for the purpose of treating M/s. Welspun as part of the domestic industry.

C. NORMAL VALUE

8. Claims of applicant

- a. Applicant has claimed that the subject country namely China is a non-market economy country under the Indian Anti-dumping Rules. Therefore, the normal value in case of China is required to be determined as per the procedure described in the para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules.
- b. As per paragraph 7, the normal value is required to be determined on any of the basis of domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export

prices from such a third country to any other country including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

- c. For the purpose of determination of normal value in case of a non-market economy country, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative. It is proposed at the time of initiation that Taiwan be taken as an appropriate market economy third country.
- d. The interested parties in their submissions have not advanced any evidence before the Authority that how and why Taiwan cannot be taken as surrogate country and as to how the normal value for China as determined by the Applicant is not acceptable. The domestic industry, therefore, requested that the unsubstantiated claims of the interested parties are required to be ignored.

9. Claims of interested parties

- a. All India Texturisers Association has submitted that the selection of Taiwan as surrogate country for the determination of normal value for China is not correct.
- b. FIASWI has claimed that the normal value for China so determined on the basis of constructed normal value in Taiwan is far from reality.

10. Examination by the Authority

- i. In anti-dumping investigations concerning imports from non-market economy countries, normal value is to be determined in accordance with paragraphs 7 & 8 of the Annexure 1 of the Anti-dumping Rules.
- ii. The Authority notes that none of the Chinese producers has responded to the exporter's questionnaire. None of the Chinese producers has claimed that they should be

granted market economy status. The Authority therefore proceeds to determine the normal value in accordance with paragraph 7 of Annexure 1 to the Rules. The normal value in China can be determined in the following manner:

- (a) on the basis of the price in a market economy third country, or
- (b) the constructed value in a market economy third country, or
- (c) the price from such a third country to other countries, including India.
- (d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

- iii. The Applicant had suggested Taiwan to be taken as the third country market economy in terms of the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules. The Authority had also proposed Taiwan as the appropriate third country market economy and had invited comments and information from all the interested parties at the time of initiation of investigation. However, in the absence of the response or information regarding the prevailing prices and costs in Taiwan, it is not possible for the Authority to determine the normal value for China under the above-mentioned (a) to (c) methods as laid down in paragraph 7 of Annexure I to the Indian Anti-dumping Rules at present. Under the circumstances, for the purpose of these preliminary findings, the Authority has no alternative but to resort to determination of normal value for China on the basis of price paid or payable in India duly adjusted, as prescribed under the rules. While arriving at the normal value based on the price payable in India, the Authority has considered the international raw material prices while the consumption norms, conversion cost and other costs prevalent in India have been considered. A reasonable return has been added to the cost of production for arriving at the price payable in

India. The normal value is, thus, for the purpose of these preliminary findings is determined as Rs. **** per MT.

D. EXPORT PRICE

11. In the application submitted for initiation of investigation, applicant had worked out export price based on the DGCI&S import data. The Authority has also obtained the import data from DGCI&S and it was found that the volume and value of the imports under Custom Tariff Heading 5402.42 (which is a dedicated code for the product under consideration) is the same as was submitted by the Applicant. The CIF export price as per the DGCI&S import data is Rs. 43053 per MT (US \$ 958 per MT). After considering price adjustments on account of marine insurance, commission, ocean freight, bank charges & port expenses, the net export price comes to Rs. *** per MT (US \$ *** per MT).

E. DUMPING MARGIN

12. For the purpose of a fair comparison between normal value and the export price, the Authority has determined both the normal value and export price at ex-factory level. Both the normal value and export price pertains to the same period. Both the prices are free of taxes. Thus, the Authority considers that the comparison made constitutes a fair comparison. Considering the normal value and the net export price determined as detailed above, dumping margin has been determined, which comes to Rs. *** per MT (US \$ **** per MT) which works out as 38% of net export price.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

13. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

The domestic industry has submitted that share of imports from China has increased manifold not only in relation to total imports but also in comparison to total demand and total production during the period of investigation as compared to the base year April 01-March 02.

The dumped imports from China have affected the domestic prices and the price undercutting and underselling is significant during the period of investigation. The market share, capacity utilization, profitability, return on investment, cash flow, growth etc. have declined over the injury investigation period. The sales of the domestic industry have increased, however the increase in sales is less than the increase in demand. The margin of dumping from china is also significant during the period of investigation, which shows the difficulties being faced by the domestic industry in disposing of the subject goods.

14. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

The views of importers and user associations are summarized below:

- i) The prices of POY have also come down for other countries.
- ii) Demand for POY is high right from the year 2001-02 as compared to indigenous production and the indigenous industry has tremendously benefited by creating shortage.
- iii) The decline in market share of the domestic industry is insignificant.
- iv) Sales volume of the domestic industry increased as a result of increase in demand.
- v) There is no injury with respect to employment and wages.
- vi) As per the balance sheets of the domestic producers, they are not making losses and most of the companies are profit-making concerns.
- vii) Inventories of the petitioners during the period of investigation were in fact lower than from the previous years.

viii) Prices of raw material are low and POY prices are high in India as compared to China where raw material prices are high and POY prices are low.

ix) Almost all the companies are increasing their capacities which indicates that the import of POY has not affected the indigenous industry at all.

15. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

An analysis of the injury parameters as envisaged under the Rules has been carried out in the following paragraphs:

- i) **Volume of Imports:** The Authority has examined the volume of imports from the subject country on the basis of the imports of subject goods as reflected by the official statistics published by the DGCI&S. It is observed that the share of subject country in total imports has increased from 2% in 2001-02 to 79% during the period of investigation. In absolute terms, the imports from the subject country has increased during the POI to a level of almost 25 times of the imports in the base year 2001-02 as is evident from the following the table:

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Imports from China (MT)	1461	1811	8693	46215	36972
Total Imports (MT)	59044	70705	33265	58382	46706
% Share	2%	3%	26%	79%	79%

- ii) **Market share of Imports:** The Authority finds that the imports from China in comparison to total demand in India have increased from a low level of 0.22% during 2001-02 to 4.65% during the period of investigation. The trend in percentage increase from year to year is as under:

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Imports from China (MT)	1461	1811	8693	46215	36972
Total Demand (MT)	678812	727431	730597	994315	795452
% Share	0.22%	0.25%	1.19%	4.65%	4.65%

- iii) **Imports from subject country as % of domestic production:** The Authority notes that imports from China as percentage of domestic production of the domestic producers have increased manifold from a level of 0.37% in the year 2001-02 to 7.34% during the period of investigation.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Imports from China (MT)	1461	1811	8693	46215	36972
Production (MT)	399348	421371	439429	629367	503493
% Share	0.37%	0.43%	1.98%	7.34%	7.34%

Thus, the imports from the China have increased not only in absolute terms but also as a share to total imports into India, market demand and also domestic production.

- iv) **Evidence on Lost Contracts:** Even though there is no direct evidence of lost contracts, it is apparent that the loss of market share and substantial increase in the volume of dumped imports do indicate that the domestic industry is suffering on account of lost sales. The authority finds that the dumped imports to the tune of 46215MT at prices as low as Rs.43053/MT (CIF Value) during the POI also clearly indicate that the domestic industry has lost sales to the dumped imports from China.
- v) **Market share of domestic producers:** The Authority finds that the market share of the domestic industry and the imports from the subject countries in the demand of subject goods in India has been as under:

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Domestic Sales	619769	656726	697332	935933	748746
Total Demand (MT)	678812	727431	730597	994315	795452
% Share	91.30%	90.28%	95.45%	94.13%	94.13%

The Authority finds that the share of the domestic producers has declined from 95.45% in 2003-04 to 94.13% during the period of investigation. It is also noted that over the same period the demand has grown by 36%. It shows that the domestic industry was not able to achieve any growth in the demand and it clearly shows that the domestic industry has been injured with respect to market share. It is also noted that the imports from China over the same period have increased

more than five times. It clearly indicates that the market share of the domestic producers as well as the growth in the market has directly been taken over by the imports from the subject country.

- vi) **Production & Capacity Utilization:** The production and capacity utilization of the domestic industry has been as under:

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Capacity (MT)	446000	497000	521000	769000	615000
Production (MT)	399348	421371	439429	629367	503493
Capacity Utilization%	90%	85%	84%	82%	82%

The Authority finds that the capacity utilization of the domestic industry has declined from 90% in the year 2001-02 to 82% during the period of investigation. Thus, the decline of 8% in the capacity utilization and on the other hand increase in imports over the injury investigation period has adversely affected the domestic industry.

- vii) **Sales Volume and Value:** The Authority notes that the increase in sales volume of the domestic industry is less as compared to the growth in demand. It clearly indicates that the domestic industry has been injured with respect to its sales.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Sales (MT)	320299	328665	339900	512145	409716
Sales Value (Rs Lacs)-Index	100	114	128	210	168

- viii) **Inventories:** The Authority notes that the level of inventories of the domestic industry has come down during the period of investigation but the increase in sales have been at loss.
- ix) **Price Undercutting & Price underselling:** The Authority has used the consistent method of comparison of weighted average net sales realization of the domestic industry with the landed value of the dumped imports. The value of the sales realization considered is net of discounts, commission, and handling/ freight charges. The comparison of domestic price with the price of the imported product is thus at the same level. Similarly, the price underselling level has been calculated on the basis of a comparison of the Non-injurious

Price (NIP) with the landed value of the dumped imports from China PR. The Authority finds that there has been a significant price undercutting as well as price underselling due to the dumped imports from China in the range of 20-30%.

- x) **Factors affecting Domestic Prices:** The Authority notes that the level of price undercutting from each of the subject countries is significant as a result of dumped imports. Further, price underselling is also evident as the landed value of imports from China is significantly lower than the non-injurious price of the domestic industry. The landed value/MT of imports from China has declined drastically during the period of investigation as compared to the year 2002-03 whereas at the same time the cost of raw material has increased as a result of the soaring crude oil prices. This clearly indicates that the effect of dumped imports on the domestic prices is much more than what is reflected from a plain analysis of the data. With regard to selling prices of the domestic industry, it is noted that the same have increased during the period of investigation as compared to the base year. The Authority also notes that the increase in the selling prices of the domestic industry is much lower as compared to the increase in costs clearly indicating that the selling prices of the domestic industry have been suppressed due to dumped imports from China. The suppressed prices of the domestic industry have led the domestic industry to incur losses during the period of investigation.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)
Landed Value from Subject Country (Indexed)	100.00	111.17	86.27	91.92
Domestic Selling Price Rs. / MT (Indexed)	100.00	111.03	120.33	131.51
Cost Rs. / MT (Indexed)	100.00	108.94	114.70	134.31

- xi) **Magnitude of Margin of Dumping:** The Authority finds that the magnitude of the margin of dumping for subject goods from the subject country has been significant.
- xii) **Employment and Wages:** The Authority notes that the domestic industry has added additional capacity and employed a number of persons. Accordingly, number of employees and wages paid to them has gone up during the injury investigation period.

- xiii) **Productivity:** The Authority finds that the productivity per employee during the period of investigation has increased as compared to base year 2001-02. It is therefore noted that the loss of productivity is not a cause of injury to the Domestic Industry.
- xiv) **Profitability:** Authority notes that the domestic industry has not been able to achieve desired level of profits during the period of investigation due to dumping by China. The Domestic Industry achieved a level of profit of 5.74% in the year 2003-2004 which however, came down to a negative level of (0.99%) during the period of investigation as may be seen from the table given hereunder:

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Profit/Loss (Rs./Unit)	****	****	****	****	****
Indexed	100	296	621	-118	-118
% Profit/Loss on Sales	1.11%	2.97%	5.74%	-0.99%	-0.99%

Authority further notes that under such circumstances the Domestic Industry had to resort to reduction in prices in line with the dumped prices of china.

- xv) **Return on Investment (Capital Employed):** The Authority notes that return on capital employed has also declined and followed the same trend as that of profitability. The domestic industry could not earn any return on its investment during the period of investigation whereas it could earn 8% return in the previous year 2003-04.
- xvi) **Actual and potential negative effect on cash flows:** The Authority finds that the cash profit / cash flow has also followed the same trend as that of the profitability and during the period and it has come down to approximately two third of the cash profit in the base year 2001-02.

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Cash Profit / Cash Flow / MT	****	****	****	****	****
Trend	100	137	178	68	68

- xvii) **Growth:** The Authority notes that though the sales volume of the domestic industry has gone up during POI, yet growth in sales volume during POI is less than the previous year and

growth in the total demand over the same period. Besides market share of the domestic industry has declined during the POI as compared to the preceding year

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Growth in Sales of the Domestic industry (Year to Year) (%)	-	4.65	6.24	33.39	6.71
Growth in Market Share of Domestic industry (Year to Year) (%)	-	-1.17	5.46	-1.35	-1.35
Growth in Demand (Year to Year) (%)	-	5.89	0.74	35.22	8.18

- xviii) **Ability to Raise Capital Investments:** The Authority finds that in view of the losses being suffered by the domestic industry on the product under consideration during the POI, the ability of the domestic industry to raise capital investment may be adversely affected in view of the negative profits of the domestic industry and declining returns during the period of investigation.

G. CONCLUSION ON INJURY:

16. In view of the foregoing the Authority confirms that:

- the quantum of imports of subject goods from the subject country have increased in absolute terms as well as in relation to total demand and domestic production in India;
- the market share of the domestic producers has come down while that of imports has increased;
- the profitability of the domestic industry for product under consideration has become negative during the period of investigation and the return on investment and cash flows have declined to a meagre level in the period of investigation.
- The capacity utilization of the domestic industry has come down;
- There is a significant and severe price undercutting as well as price underselling;
- The margin of dumping from the subject country is significant.

The Authority therefore concludes that the domestic industry has suffered material injury as envisaged under the Rules.

H. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

17. Effect of dumped imports

Between 2001-02 and the POI, the dumped imports from subject country as percent of total import of subject goods have increased sizably from 2% to 79%. The percentage share of imports from china in comparison to total demand has also been going up over the investigation period. This increased from 0.22% in 2001-02 to 4.65% in the POI. While examining the price effect i.e. whether the dumped imports have significantly undercut the price of the subject good in India, the Authority found that the landed value of the subject goods from china was lower than the selling price of the domestic industry thereby undercutting the selling price of the domestic industry significantly. It is found that the price undercutting and the pricing behaviour of landed value of imports has forced the domestic industry to keep the domestic prices at unremunerative level even below the cost of production thereby adversely effecting the financial condition of the domestic industry. The domestic industry could not increase the selling price to recover the full increase in cost of production due to dumped imports and had to suffer financial losses during the POI. The undercutting along with price suppression in effect eroded the profitability of the domestic industry. The domestic industry has suffered material injury due to dumped imports from china during the POI.

18. EFFECT OF OTHER FACTORS

- a) **Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers:** The Authority did not find any trade restrictive practices followed by the Indian producers and other competing industries. As regards the Domestic Industry's inability to fill the gap between the domestic demand and their own production, it is observed that the imposition of anti-dumping duties does not amount to any kind of restriction on suppliers and producers for supplying the subject goods in the domestic market, which could have contributed to the injury to the domestic industry. Moreover, it is also noted that the domestic industry has unutilized capacity to cater to the local demand if the competition in the market take place at a fair price.

- b) **Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption:** It is noted that there is no contraction in the demand during the period under consideration. On the contrary, the overall demand has increased during the POI. Therefore, the possible decline in demand is not a factor, which could have caused injury to the domestic industry.
- c) **Technology:** None of the interested party has submitted any evidence that the technology is a factor of injury to the domestic industry.
- d) **Export performance:** The Domestic Industry has exported the subject goods during the period of investigation as well as during previous years. The Authority notes that the export performance of the domestic industry has shown improvement. The profitability of the domestic and exports sales have been segregated for the purpose of the injury examination. Therefore, injury caused due to exports (if any) has not been attributed to the performance of the domestic industry in the domestic market. The export details by the domestic industry have been given in the following table:

	2001-02	2002-03	2003-04	POI (15 Months)	POI Annualized
Exports (MT)	9879	13115	17862	24260	19408
Exports (Rs. Lacs)	****	****	****	****	****
Indexed	100	145	197	305	244

- e) **Productivity:** The productivity of the domestic industry has improved during the period of investigation as compared to the base year 2001-02. The productivity *per se* could not be the cause of injury to the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

19. The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to facilitate re-establish a situation of open and fair competition.
20. The Authority also recognizes that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the

products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would eliminate the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help in maintaining availability of wider choice of the subject goods to the consumers.

J. Conclusions:

21. The Authority has, after perusing and considering the foregoing, come to the conclusion that:
- a. Subject goods originating in or exported from subject country have been exported to India below their normal values.
 - b. The domestic industry has suffered material injury.
 - c. The injury has been caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods originating in or exported from the subject country.
 - d. The Authority thus considers necessary to recommend provisional anti-dumping duty on imports of subject goods falling under Chapter 54 of Customs Tariff Act originating in or exported from the subject country.

K. Recommendations:

22. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a preliminary investigation into dumping, injury and causal link between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having provisionally established positive dumping margin against the subject country, as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury pending completion of the investigation.

23 Therefore, Authority considers it necessary to recommend provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

24 Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, provisional antidumping duty equal to the amount indicated in Column 9 of the table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of Partially Oriented Yarn (POY) falling under chapter 54 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from China.

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402.42	Partially Oriented Yarn –	Any	China PR	Any	Any	Any	486	MT	US\$
2.	-do-	All Types -do-	-do-	Any	China-PR	Any	Any	486	MT	US\$

L. FURTHER PROCEDURE:

25 The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- Exporters, Importers, Applicant and other interested parties known may make known their views, within forty days(40) from the date of these preliminary findings;
- The Authority would conduct further verifications to the extent deemed necessary;
- The Authority would provide opportunity to all interested parties for oral submissions, for which the date and time shall be communicated to all known interested parties separately;
- The Authority would also disclose essential facts before announcing final findings in terms of Rule 16 of the Anti-dumping Rules.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority